जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 | वर्षः 51 | संख्याः 31 | प्रभात | कोटा, शुक्रवार, 14 नवम्बर, 2025 | कोटा/24/2012-14 | पृष्ठ 6 | मूल्य 2.50 रु.

क्या नीतीश कुमार, लालू यादव का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, साल भर के लिए मु.मंत्री पद संभालेंगे

लालू यादव की सोच है कि अगर नीतीश ने पाला बदला तो अतिरिक्त लाभ यह होगा कि केन्द्र में मोदी सरकार भी संकट में आ जाएगी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 नवंबर। सारी नज़रें अब नीतीश कुमार पर टिकी हैं, उस व्यक्ति पर जो 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर "राजा" बनना चाहता है।

उन्हें कभी "सर्वाइवर इन चीफ़" तो कभी "पलटू राम" कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बार-बार अपनी राजनीतिक निष्ठा बदली है, कभी भाजपा के साथ, फिर लालू यादव के साथ, फिर दोबारा भाजपा के साथ, और यह सिलसिला जारी रहा है।

इस बार भी वे भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए लालू यादव के साथ बातचीत में जुटे हैं। लेकिन भाजपा द्वारा अब तक उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न करने से तनाव और असंतोष का माहौल बन गया है। अगर भाजपा और जद (यू) का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा, तो इसका एक बड़ा कारण कार्यकर्ताओं में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रत्याशी न बनाए जाने से उपजा आक्रोश भी हो सकता है, और इसकी जिम्मेदारी भाजपा पर आ सकती है।

- जैसा कि विदित ही है, दिल्ली में मोदी सरकार को जीवित रहने के लिए चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार का समर्थन अनिवार्य है।
- ऐसा माना जा रहा है कि जदयू व भाजपा का सपोर्ट बेस काफी सिकुड़ा है। हालांकि, एग्ज़िट पोल कुछ भी आकलन लगा रहे हों, दोनों पार्टी गत चुनाव के मुकाबले काफी कमज़ोर होंगी, इस बार।
- एनडीए के लिए यह शुभ समाचार नहीं है।
- अतः एनडीए को यदि बहुमत नहीं मिल पाया तो लालू के नीतीश कुमार को दिए गए प्रस्ताव में काफी दम आ जाएगा।

लालू यादव की ओर से नीतीश कुमार के लिए प्रस्ताव अब भी खुला है, वे आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन में शामिल हों और एक साल के लिए मुख्यमंत्री बनें। इसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार के बेटे को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लालू यादव की गणना यह है कि अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो इसका सीधा असर नरेन्द्र मोदी की केन्द्र सरकार पर पड़ेगा। भाजपा ने पिछला लोकसभा चुनाव 240 सीटों के साथ जीता था, जबकि एग्ज़िट पोल्स ने उसके लिए 400 सीटों का अनुमान लगाया था, इसलिए अब भाजपा अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर निर्भर है।

भाजपा पिछले छह महीनों से बिहार चुनाव को सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित करने में लगी हुई है और हर हाल में सत्ता में लौटने की उम्मीद कर रही है।

लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोगों का कहना है कि, भाजपा और जद (यू) दोनों के समर्थन आधार में बड़ी गिरावट आई है। यह सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए बुरी खबर है, भले ही एग्ज़िट पोल्स एक चमकीली तस्वीर पेश कर रहे हों। इतिहास बताता है कि बिहार के मामले में एग्ज़िट पोल्स शायद ही कभी सही साबित हुए हों।

तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार की जान ली

जयपुर, 13 नवम्बर। हरमाड़ा थाना इलाके के सीकर हाईवे पर गुरुवार को फिर एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक की जान ले ली और दूसरे को गंभीर रुप से घायल कर दिया। हादसे के बाद डंपर चालक गाड़ी छोड मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भिजवाया। वहीं, मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर में भिजवाया।

- जयपुर-सीकर हाईवे पर बाइक को कुचलने के बाद चालक डंपर छोड़कर भाग गया।

दुर्घटना थाना वेस्ट में तैनात हेड कॉन्स्टेबल भरत सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश निवासी सोनू (30) अपने साथ गौरीशंकर (29) निवासी बरवाड़ा सामोद निवासी के साथ सोलर प्लांट लगाने का काम करता है। दोनों दोस्त गुरुवार सुबह साढ़े 10 बजे अपने किसी काम से सीकर हाईवे पर स्थित टोडी मोड़ तिराहे से होते हुए चौमू से जयपुर आ रहे थे। इसी दौरान टोडी मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से बाइक को जोरदार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अगर सरकार नहीं बनी तो नीतीश का हम क्या करेंगे'

भाजपा में इस असमंजस की स्थिति को लेकर काफी सोच व चिंतन चल रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 नवम्बर। बिहार में 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से ठीक पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेतृत्व में असमंजस और बेचैनी का माहौल है। चिंता इस बात की है कि अगर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरती, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कैसे निपटा जाए।

अत्यधिक महत्वपूर्ण बिहार विधानसभा चुनाव को भाजपा के लिये प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा था, लेकिन इसके नतीजे आने से पहले ही पार्टी के राज्य और केन्द्रीय नेतृत्व के बीच रणनीति, नेतृत्व और भविष्य के गठबंधनों को लेकर पुराने मतभेद, अप्रत्याशित रुप से, फिर उभर आए हैं।

भाजपा के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, "नीतीश फैक्टर" ने बिहार भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) दोनों के भीतर गहरी हलचल पैदा कर दी है। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि मुख्य विवाद उस राजनीतिक जोखिम को लेकर है, जो भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा न बनाकर उठाया, जबकि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और मतदाता जमीनी स्तर पर उनके जबरदस्त समर्थक थे।

- इस संभावना से भाजपा नेतृत्व में भी मतभेद उभरने लगे हैं, पार्टी की चुनावी रणनीति को लेकर।
- साथ ही भाजपा व आरएसएस में भी इस विषय से खिंचाव पैदा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करने का निर्णय सही था।
- भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने पक्का मन बना लिया था कि नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए और भाजपा को बिहार में अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी चाहिए।
- भाजपा के रणनीति विशेषज्ञ भी अब यह स्वीकार कर रहे हैं कि अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है और कांग्रेस का प्रदर्शन भी कुछ बेहतर होता है तो मोमैन्टम तेजस्वी यादव के पक्ष में हो जाएगा, इसलिए आरजेडी बड़ा आक्रामक रूख अपना रही है और भाजपा को किसी भी तरह से राजनीतिक चालबाजी का मौका नहीं देना चाहती तथा जल्द से जल्द बहुमत प्रदर्शित करना चाहती है।

पटना में भाजपा के एक शीर्ष पदाधिकारी ने स्वीकार किया कि नेतृत्व ने शायद नीतीश कुमार की निरंतर राजनीतिक प्रासंगिकता को कम करके आंका। उन्होंने कहा, "केन्द्रीय नेतृत्व बिहार में भाजपा की स्वतंत्र पहचान स्थापित करने के लिए कटिबद्ध था।" लेकिन अब पीछे मुड़कर देखें तो नीतीश को अलग रखना महंगा साबित हो सकता है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि अगर नतीजों के बाद संख्या बल की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सख्त सुरक्षा इंतजामात के बीच सुबह आठ बजे मतगणना शुरु होगी पटना में

भाजपा ने जीत की खुशी में आयोजित होने वाले आयोजनों के लिए भारी मात्रा में लड्डुओं का ऑर्डर दिया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 नवम्बर। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले, जहाँ एक ओर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं, दूसरी ओर जश्न की तैयारियाँ भी जोरों पर हैं। भाजपा ने अपनी संभावित जीत के जश्न के लिए लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया है।

पटना में माला बेचने वाले भी उम्मीद कर रहे हैं कि जीत चाहे किसी भी पक्ष की हो, उनका कारोबार तो अच्छा ही रहेगा।

मतगणना शुक्रवार, 14 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरु होगी। अगर एग्ज़िट पोल सही साबित हुए और सत्तारुढ़ एनडीए (जेडीयू-भाजपा गठबंधन) की लहर चली, तो शुरुआती रुझान जल्द ही साफ हो सकते हैं।

- माल बनाने वाले भी बहुत खुश हैं, चाहे जो जीते और जो हारे, उनका धंधा खूब चलेगा शुक्रवार को।
- सुरक्षा व्यवस्था दो चक्रों में की गई है, अंदर का चक्र केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल को सौंपा गया है तथा बाहरी चक्र राजकीय पुलिस संभालेगी।
- वोटिंग मशीनें डबल लॉक सिस्टम से सुरक्षित कर स्ट्राँग रूम में रखी गई हैं तथा 7.4 करोड़ मतदाताओं का निर्णय दोपहर तक सामने आ जाएगा।

इसी बीच, विपक्ष ने गुरुवार को एक बार फिर "चुनावी गड़बड़ी" की आशंका जताई है और कहा है कि हाल के समय में एग्ज़िट पोल तो कई बार गलत साबित हुए हैं।

नतीजे तय करेंगे कि क्या राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार एक बार फिर शपथ लेंगे, या फिर विपक्षी महागठबंधन, जिसमें इंडिया ब्लॉक की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नई भर्ती में 2021 के अभ्यर्थियों को आयु में छूट नहीं

जयपुर, 13 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक से प्रभावित एसआई भर्ती-2021 में शामिल रहे अभ्यर्थियों को साल 2025 की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने के संबंध में एकल पीठ की ओर से दिए आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। अदालत ने माना कि एकलपीठ की ओर से अपने आदेश में की गई टिप्पणियां अनावश्यक थीं। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिए।

- हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाई।

अपील में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि एकलपीठ के समक्ष केवल यह विचारणीय बिंदु था कि एसआई भर्ती-2021 में शामिल हुए अभ्यर्थियों को नई भर्ती में आयु सीमा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी सरकार की लाल किले के पास हुए आतंकवादी विस्फोट पर प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा संयमित नहीं थी?

द वायर के संपादक सिद्धार्थ वर्धराजन ने इस संयमित प्रतिक्रिया का कारण ट्रंप व अमेरिका की अपरिपक्व सोच बताया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 नवम्बर। दिल्ली में सोमवार को लाल किले के पास हुये बम विस्फोट में 13 लोगों की मौत के बाद मोदी सरकार की प्रतिक्रिया बेहद संयमित रही। मंगलवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केवल एक सामान्य प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें न तो किसी संगठन का नाम लिया गया, न ही किसी देश पर उंगली उठाई गई। यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस कड़े बयान से बिल्कुल अलग थी, जो उन्होंने 12 मई को "ऑपरेशन सिंदूर" को "रोकने" के तुरंत बाद दिया था:

"पहला, अगर भारत पर आतंकी हमला होता है, तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा...

"दूसरा, भारत किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत उन आतंकी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा, जो परमाणु धमकियों की आड़ में विकसित हो रहे हैं...

"तीसरा, हम आतंकवाद को पोषित करने वाली सरकार और आतंक के सूत्रधारों के बीच कोई फर्क नहीं करेंगे।

- शायद सरकार को आशंका थी कि यह कहना मुश्किल है कि ट्रंप इस विध्वंसकारी गतिविधि का कौन सा पहलू पकड़ कर अनर्गल बयानबाजी शुरु कर दें, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था।

"द वायर" के सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजन लिखते हैं, दिल्ली धमाके के बाद दिखाई गई इस संयमित प्रतिक्रिया का कारण शायद यह है कि घटना की पूरी तस्वीर अभी साफ़ नहीं है। हालाँकि यह सवाल भी उठता है कि अगर स्थिति इतनी अस्पष्ट थी तो प्रधानमंत्री ने पहले से इतना आक्रामक और अव्यावहारिक रुख क्यों अपनाया था। वे यह भी लिखते हैं कि यह इसलिए भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री को पता है कि जब भारत ने पहले पहलगाम हमले के बाद सैन्य कार्रवाई की थी तो विश्व समुदाय, खासकर अमेरिका और उसके राष्ट्रपति, ने कैसी प्रतिक्रिया दी थी।

सरकार की चुप्पी के बावजूद, मीडिया के कुछ हलकों में "तुर्की एंगल" को लेकर अटकलें शुरू हो गईं। इस पर अंकारा (तुर्की) ने कड़ा बयान जारी करते हुए "भारत और तुर्की के द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही दुष्प्रचार मुहिम" की कड़ी निंदा की।

विजयता सिंह कहती हैं, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा जिस "आतंकी मॉड्यूल" की जांच की जा रही है, उससे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत ने लद्दाख में 1962 से बंद एयर बेस चालू किया

नयी दिल्ली, 13 नवम्बर। भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी सैन्य तैयारियों को पुख्ता करते हुए चीन के साथ 1962 की लड़ाई के बाद से बंद पड़े सामरिक रूप से महत्वपूर्ण न्योमा एयर बेस को एक बार फिर से सक्रिय रूप से चालू कर दिया है।

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने बुधवार को खुद वहां जाकर इसका उद्घाटन किया। एयर चीफ मार्शल वायु सेना के भारी भरकम मालवाहक विमान सी-130 जे से वहां उतरे और एयर बेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ वायु सेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख भी थे।

- वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सामारिक रुप से महत्वपूर्ण एयर बेस का उद्घाटन किया।

दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश सरकार इस्लामिक ताकतों के आगे झुकी तथा फरवरी 2026 में चुनाव कराने की घोषणा की

बांग्लादेश की इस्लामिक ताकतें नहीं चाहती थीं कि अन्य राजनीतिक दलों को मौका मिले चुनाव प्रचार करने का या संगठित होने का और यकायक चुनाव करा दिये जाएं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 नवंबर। पड़ोसी देश बांग्लादेश फरवरी 2026 में आम चुनाव कराने जा रहा है। इसी के साथ एक "राष्ट्रीय चार्टर" पर जनमत संग्रह भी कराया जाएगा। फरवरी में चुनाव कराने की इस अचानक घोषणा से कई लोग हैरान हैं, क्योंकि इसके लिए तैयारी का समय बहुत कम बचा है।

वर्तमान अंतरिम सरकार, जिसके मुखिया मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस हैं, एक तरह से बांग्लादेश की राजनीति में इस्लामिक ताकतों के दबाव में झुकती दिख रही है, क्योंकि इन्हीं तत्वों ने जल्दी चुनाव कराने की मांग की थी, ताकि मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियाँ अचंभे में पड़ जाएँ और तैयारी न कर सकें।

भारत के दृष्टिकोण से बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार का गठन स्वागत योग्य होगा, लेकिन अंतरिम सरकार के कुछ कदम, खासकर इस्लामिक और आतंकी संगठनों को फिर से बांग्लादेश में पैर जमाने की अनुमति देना, भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चिंता का कारण बन रहे हैं।

हाल की रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी मसूद अजहर का एक शीर्ष सहयोगी हाल ही में बांग्लादेश में था। उसने भारत-बांग्लादेश सीमा के कुछ हिस्सों का दौरा भी किया, संभवतः भारत के खिलाफ किसी गतिविधि की योजना के लिए।

- जैसा कि विदित ही है, प्रमुख राजनीतिक पार्टी अवामी लीग पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका नहीं दिया गया है उन्हें।
- गत वर्ष विद्यार्थियों के एक आंदोलन में अवामी लीग की सरकार का तख्ता पलट कर नया भ्रष्टाचार युक्त सिस्टम स्थापित करने का संकल्प लिया था।
- अभी छात्र आंदोलन भी चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं हैं व नया संविधान बनाना चाहते हैं, जिससे बहु जाति, बहु धर्म, बहु भाषा से सुसज्जित राष्ट्र बने बांग्लादेश।
- पर, किसकी चलेगी, राष्ट्रवादी छात्र आंदोलन की या इस्लामिक ताकतों की, जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से सहयोग करना चाहती है, इस्लामिक एकता के नाम पर।

ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश में अपने भारत-विरोधी षड्यंत्रों के लिए फिर से प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

वर्तमान सत्तारूढ़ तत्व कट्टर भारत-विरोधी हैं और उन्होंने पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों को बांग्लादेश में अपनी पकड़ मज़बूत करने में मदद दी है।

इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने मांग की है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी संभव हैं, जब आवामी लीग पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए। अवामी लीग, जिसने देश की आज़ादी के बाद अधिकांश समय शासन किया, को सरकार के खिलाफ सफल जनविद्रोह के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था।

पिछले वर्ष हुए छात्र आंदोलन ने अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेख हसीना भारत में शरण लेकर अब यहीं रह रही हैं। बांग्लादेश सरकार ने भारत से उन्हें सौंपने की मांग की है, ताकि उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाई जा सके।

बांग्लादेश में छात्र आंदोलन और व्यापक हिंसा के बाद, आंदोलनकारी छात्र नेताओं और अन्य समूहों ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुणे में 25 गाड़ियां टकराईं, 9 की मौत

पुणे, 13 नवम्बर। पुणे के बाहरी इलाके में नवले ब्रिज के पास गुरुवार शाम एक ट्रक का ब्रेक फेल होने से 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ट्रक सबसे पहले एक कार से टकराया। कार आगे जा रहे कंटेनर से भिड़ गई और उसमें आग लग गई। ट्रक भी जल गया।

- ब्रेक फेल होने से ट्रक कार से टकराया, जो कंटेनर से टकराई और आग लग गई, फिर और गाड़ियां टकराती गईं।

हादसे में कार सवार 5 लोग जिंदा जल गए। ट्रक ड्राइवर समेत 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 20 लोग घायल भी हुए हैं।

पुलिस के मुताबिक हादसा पुणे-नासिक हाईवे पर भोरगांव के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से कंटेनर और ट्रक के बीच दब

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)